the State level. This has been done with a view to achieving higher consumption of fertilisers, particularly in the rainfed areas and other areas where the existing level of consumption is low. The lead manufacturers would also be associated with the State Departments of Agriculture, both at the district as well as State levels in assessing the fertiliser requirement and also taking up other measures like demonstrations of fertiliser use and training of fertiliser dealers & farmer in the handling and use of chemical fertilisers and building up fertiliser statistics.

Requirement of Fertilizer for Rabi Season

3412. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the estimated requirement of fertilizer for the current Rabi season; and

(b) what is the total production of the fertilizer during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) The assessed gross requirement of fertiliser nutrients for Rabi, 1986-87 (October, 1986 to March, 1987) season is 55.13 lakh tonnes of N+P+K.

(b) The likely production during Rabi, 1986-87 season is 37.64 lakh tonnes of N+P. There is no indigenous production of K.

कृषि मंत्रालय में स्वायत्त संस्थानों में राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

3413. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और अन्य सहकारी निकायों जैसे स्वायत्त संस्थानों पर भी लागू होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो हाल में कृषि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में और कृषि मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में राजभाषा अधिनियम और नियमों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सरकार ऐसे स्वायत्त संस्थानों और सहकारी निकायों में राजभाषा अधिनियम को लागू करने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एक पंजीकृत सोसायटी है तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से राजभाषा विभाग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियम परिषद् पर लागू नहीं होते। जहां तक सहकारी सोसायटियों का संबंध है चूंकि यह राज्य का विषय है और ऐसी समितियों पर राज्य की सहकारी समितियों संबंधी अधिनियम लागू होते हैं, अतः वे राज्य की एतत्सम्बन्धी नीति का अनुसरण करती हैं। तथापि राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संगठनों जैसे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोपरेटिव तथा कृषक भारती कोपरेटिव द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) हालांकि राजभाषा अधिनियम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पर लागू नहीं होता तो भी सरकार की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा इसके संस्थानों में राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गये नियमों के सांविधिक प्रावधानों को स्वेच्छा से कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न किये जाते रहे हैं। दिनांक 29 अगस्त, 1986 को हुई कृषि मंत्रालय हिन्दी सलाह-